नईदुनिया

अवैध अप्रवासियों की वापसी के तरीकों पर है आपत्ति

डॉ. विश्वास तिवारी

बीस जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं चाहे वह दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना हो, कनाडा, पनामा नहर और गाजा को अपने अधीन लेने का विचार हो या फिर अवैध तरीके से अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने का हो। यह विडंबना ही है कि पूरे विश्व को मानव अधिकारों एवं आदर्श जीवन मूल्यों की नसीहत देने वाले अमेरिका ने विभिन्न देशों के अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने को बलपूर्वक अंजाम दिया। इस पर हमारे देश की संसद में जो आपत्ति और आक्रोश जताया गया, वह उचित ही है। किसी भी देश को अधिकार है कि वह अपने देश में अवैध तरीके से प्रवेश करने वालों को उनके देश वापस भेज दे, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं की वह उन्हें हथकड़ी और बेड़ी लगाकर अमानवीय तरीके से भेजे। पिछले दिनों अमेरिका ने अपने सैन्य विमान से जिन 104 भारतीयों को अमृतसर के हवाई अड्डे पर भेजा (और 487 अन्य भारतीय अभी फिर भेजे जाने है) उन्हें 20 घंटों की हवाई यात्रा के दौरान हथकड़ी पहनाएं रखा और उनके पैरों को जंजीरों से बांधे रखा और सैन्य विमान होने के कारण उन्हें पेशाब तक करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सैन्य विमान में एक ही बाथरूम होता है। आखिर यह सब करने की क्या जरूरत थी जब वह विमान में चढ़ गए थे तो उनके भागने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वो भी जब भारत ने इस कार्यवाही का समर्थन किया था और डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना मित्र देश कहते है। अवैध अप्रवासी भी अमेरिका से बेदखल किए जाते समय समान्य गरिमा के तो हकदार थे। इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी, अवैध अप्रवासियों में महिलाएं और बच्चे भी थे और उनके साथ भी संवेदनहीनता दिखाई गई। अमेरिका ने भारत के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह लोग खूंखार अपराधी या आतंकवादी हो। अमेरिका में पहले भी भारतीय अवैध अप्रवासियों को ओबामा और बाइडन के कार्यकाल में वापस भेजा जा चुका है, लेकिन यह पहली बार है कि उनके साथ अमाननीय व्यवहार हुआ है। भारत को इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यह सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए अवैध अप्रवासियों को अपने देश से बाहर करने को चुनावी मुद्दा बनाया था और वह अब यह बताना चाह रहे है कि वह अपने हर वादे को पूरा कर रहे है, लेकिन यदि ट्रंप चाहते है कि भारत उनके हर मुद्दों पर चाहे वह आयात शुल्क कम करना हो या ईलान मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में प्रवेश दिलाना हो तो उन्हें भी भारत के मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखानी होगी। इस समय ट्रंप केवल एक सिद्धांत पर काम कर रहे है कि 'अमेरिका केवल अमेरिकन्स' का है मगर वह यह भूल रहे है कि इस देश का निर्माण, बाहरी आबादी से हुआ है। ट्रंप दरअसल पूर्व राष्ट्रपति से बड़ी लकीर खींचना चाहते है। बाइडन प्रशासन ने पिछले वित्तीय वर्ष में ढाई लाख से अधिक अवैध अप्रवासियों को अपने देश से निर्वासित किया था जो कि साल 2014 के बाद से निर्वासन का उच्चतम रिकार्ड है, लेकिन ट्रंप अवैध अप्रवासियों को सेना के विमानों से भेज रहे है, जबकि बाइडन ने उन्हें चार्टर फ्लाइट से भेजा था। अब इसमें सवाल यह है कि क्या अमेरिका में भारत के दूतावास और भारतीय विदेश मंत्रालय इस तरह की अमाननीय कार्यवाही से अनभिज्ञ थे?

एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर के करीब एक करोड़ दस लाख लोग इस समय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे है। इनमें से काफी सारे लोग भारत के भी है। इस समय अमेरिका ने करीब 18,000 भारतीयों को वापस भेजने का फैसला किया है, क्योंकि इनके पास वहां रहने के लिए उपयुक्त दस्तावेज नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध अप्रवासी अमेरिका में ही रहते है, उसके बाद रूस और उसके बाद भारत में रहते है।

एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर के करीब एक करोड़ दस लाख लोग इस समय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे है। इनमें से काफी सारे लोग भारत के भी है। इस समय अमेरिका ने करीब 18,000 भारतीयों को वापस भेजने का फैसला किया है, क्योंकि इनके पास वहां रहने के लिए उपयुक्त दस्तावेज नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध अप्रवासी अमेरिका में ही रहते है, उसके बाद रूस और उसके बाद भारत में रहते है। अमेरिका में सबसे ज्यादा अप्रवासी मेक्सिको से आते है। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों से काफी अच्छे है और इसलिए ही भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी प्रशासन को इस काम में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में पाया जाता है तो हम उसकी नागरिकता का सत्यापन करा कर हम उसे वापस भारत में ले लेंगे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई निश्चित रूप से निंदनीय है अवैध घुसपैठ का शिकार खुद भारत भी है। लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ-साथ हजारों रोहिग्या यहां वर्षों से रह रहे है और अपना फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर मुफ्त का अनाज ले रहे है। ऐसे घुसपैठिएं भारत देश से प्यार भी नहीं करते और अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते है। अदालती निर्देश के बावजूद सरकार राजनयिक स्तर पर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच बातचीत कर रही है कि वे अपने अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को ले जाए। अदालती निर्देश के तहत अगर सरकार चाहे तो सेना के जरिए उन्हें जबरदस्ती उनके देश भेज सकती है। यह घटना अमेरिका में वैध रूप से रह रहे भारतीय समुदाय को भी प्रभावित करेगी और भारत की प्रतिष्ठा को भी। वैध तरीकों से रह रहे भारतीयों ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अमरिका में अच्छी जगह बनाई है और वहां टैक्स के रूप में पूरा और बड़ा योगदान देते है। भारत सरकार भी इस तथ्य को अच्छी तरह समझती है कि समस्या की मूल जड़ अवैध प्रवासियों का वापस आना नहीं, बल्कि उनका अवैध तरीके से अमेरिका जाना है। ऐसी क्या सुविधाएं उन्हें भारत सरकार नहीं दे पाई कि वह अपनी जान-जोखिम में डालकर अवैध तरीके से अमेरिका जाने को मजबूर हो गए?

अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले भारतीय 'डुनकी रुट' जिसे डंकी रुट भी कहा जाता है का इस्तेमाल करते है। इस ही नाम से राजकुमार हिरानी फिल्म भी बना चुके है जिसमें शाहरूख खान ने अभिनय किया था। इस रुट से जाने वाले यात्री अलग-अलग देश से होते हुए अमेरिका पहुंचते है जिसमें कई बार इनकी जान भी चली जाती है। भारतीय अमेरिका में अवैध तरीके से पहुंचने के लिए कनाडा से घुसपैठ करते है और चीनी नागरिक मैक्सिको से घुसते है। विदेश मंत्रालय बता रहा है कि ये पंजाबी लोग अमेरिका जाने के सपने को पूरा करने के लिए 45 लाख रुपये खर्च कर सकते है वो गरीब नहीं हो सकते, जबकि सच यह है कि यह लोग अपनी जमीन, घर बेचकर और लोन लेकर इन पैसों का इंतजाम करते है। अब भारत सरकार को यह प्रयास करना होगा कि लोगों को विदेश पहुंचाने वाले ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। ताकि इस प्रक्रिया पर रोक लगे और इसेके साथ-साथ नए अवसर बनाने पर भी ध्यान देना होगा। तभी लोगों को यह समझ आएगा कि इतना पैसा गंवाकर और जान-जोखिम में डालकर विदेश जाने का कोई मतलब नहीं है। अब अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध अप्रवासियों की स्थिति ऐसे हो गई है कि अब 'वो ना घर के रहे ....न घाट के'।

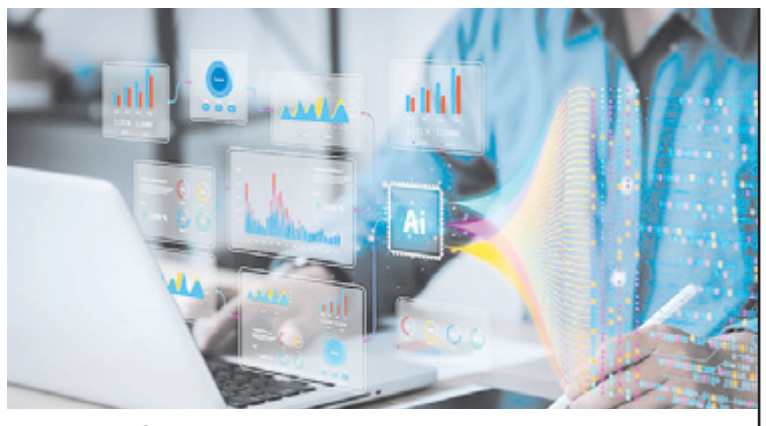

एआई की सौगात : संभावनाएं और चुनौतियाँ

गिरीश्वर मिश्र

एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग की दिशा में वैज्ञानिकों और तकनीकविदों ने कमाल की बढ़त हासिल की है और उनके अभियान का क्रम लगातार जारी है। एआई बड़ा संक्रामक है और देश-काल की सीमाओं को तोड़ते-फ़लांघते वह जल, थल और अंतरिक्ष हर कहीं मनुष्य की अप्रत्याशित रूप से त्वरित पहुँच का विस्तार करता जा रहा है। वैसे तो एआई भी एक नैसर्गिक यानी स्वाभाविक मानवीय बुद्धि का ही करिश्मा है परंतु आज जिस गति से सबकुछ में निर्बाध दखल देते हुए इसके ज़रिए जो बदलाव लाए जा रहे हैं वे दुनिया का नक़्शा ही बदल रहे हैं। निर्माण अपने निर्माता की नियति तय करता दिख रहा है।

आज वर्चुअल और डिजिटल को इस तरह स्थापित किया जा रहा है कि उनके आगे सत्य और यथार्थ हिलने-काँपने लगा है। मनुष्य सत्य और असत्य (झूठ) पर भरोसा करता आ रहा है। सत्य अर्थात् वह जिसका अस्तित्व है (सत्) परन्तु अब नाना प्रकार के सत्य अस्तित्ववान हो रहे हैं जिनमे अपनी पसंद से चुनना होता है पर जिस भी संस्करण के सत्य उभर रहे हैं उनके पीछे आ आई का हाथ ज़रूर होता है। वैसे तो किसी भी तरह के चुनाव का आधार मुख्य नियामक होता है ताकि होड़ लेते विभिन्न सत्यों के कई प्रत्याशियों के बीच असली या उपयोगी सत्य को खोज कर पहचाना जा सके। सत्य के साथ स्थिरता, निरंतरता और सातत्य या फिर अपरिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता जैसे मानक भी स्वाभाविक रूप से जोड़ दिए जाते रहे हैं। परम और नित्य सत्य की परिकल्पना हमें ईश्वर के क़रीब पहुँचा देती है।

आज जब सत्य के निर्माण की छूट मिल रही है तो उसके कई परिणाम सामने आ रहे हैं। सारी क़ानूनी मशीनरी सत्य का बाजार चला रही है। वह प्रमाण और साक्ष्य के माध्यम से मुकदमा चलने के दौरान मुल्तबी सत्य को अपने बल पर सत्य के खाँचे में फिट कर देती है। वकील और गवाह मिल कर सत्य रचते और तय करते हैं और वह जज के सत्यबोध से मेल खा जाए तो वह सुच्चा या निखालिस सच बन जाता है। यह दृष्टि सत्य की अस्थिरता या सापेक्षिकता और अन्ततः बहुलता की तरफ़ ले जाती है जिसके अच्छे-बुरे दोनों तरह के परिणाम हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत आगे जा रही है। वह वास्तविक बुद्धिमत्ता के उपयोग के अवसरों और अभ्यासों को जिस तरह बदल रही है उससे हमारी आदतें, व्यवहार शैली और जीने का अंदाज़ सबकुछ बदलता जा रहा है। इस तरह का व्यापक नवाचार हमारी अपने बारे में समझ को भी बदल रहा है। मनुष्यता के स्वभाव, बच्चों के पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई आदि मनुष्य के रूप में निर्माण जैसे जरूरी उपायों के स्वरूप को प्रभावित कर रहा है। जीवन में एआई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर तरफ़ उपस्थित है। पिछले कुछ दिनों में डीप फेक और साइबर अरेस्ट जैसी घटनाओं ने एआई के उपयोग के अतिरेक से पैदा हो रही तमाम मुश्किलों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनका संबंध जीवन की गुणवत्ता से है। एआई की पहुंच का विस्तार या रेंज बढ़ता ही जा रहा है। निजी जीवन में उसकी दखल दुरभिसंधि, भयादोहन, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, आर्थिक घोटाले और व्यापार जगत सबको संत्रस्त करने वाला साबित हो रहा है।

एआई के उपयोग से काम में सुभीता, शीघ्रता और मात्रा को ध्यान में रखते हुए आज विभिन्न देशों में अपनी एआई की क्षमता बढ़ाने के लिए होड़ मची हुई है। भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। औद्योगिक क्रांति जैसी क्रांति का लाभ न पाकर हम अब यह सोच रहे हैं कि एआई क्रांति से बड़ी लम्बी छलांग लगा लेंगे-यह आकर्षक पर ख़तरनाक हो सकता है।

कुछ दिन पहले भारतीय मूल के नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वेंकी रामकृष्णन ने जयपुर में बोलते हुए स्पष्ट रूप से एआई की संभावनाओं के साथ इससे जुड़े बड़े ख़तरों की ओर ध्यान खींचा, शायद उससे निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता काफ़ी न होगी। उसके किए समानुभूति, इतिहास और संस्कृति की समझ की भी दरकार होगी। बिना उस व्यापक संदर्भ के हमारे समाधान छिछले, संकुचित और नुक़सानदेह हो सकते हैं। सबकुछ तकनीक विशारदों पर नहीं छोड़ा जा सकता। एआई के नैतिक और सामाजिक आयाम भी हैं। शिक्षा में वे मानविकी और विज्ञान परौद्योगिकी दोनों को महत्व देने की वकालत कर रहे थे। तकनीकी और मानविकी के बीच की खाई पाटी जानी चाहिए। एआई का नियंत्रित उपयोग वहां हितकारी हो सकता है वहां कार्य क्षमता, उत्पादकता आदि ज़रूरी हों। हमें पूरा सच देखना होगा। प्राचीन ऋषियों ने ऐसे ही नहीं कहा था कि स्वर्ण के ढक्कन से सत्य का मुख ढंका हुआ है- हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यासपिहितम् मुखम। अतीत से विच्छिन्न, मूलहीन सभ्यता की नई इबारत लिखने वाली सोच अधूरी है। उसके हिसाब से हम सब एक डाटा प्वाइंट होते जा रहे हैं। समाज और संस्कृति की स्मृति को मिटा देना बड़ी त्रासदी है। हमें इसके प्रति आगाह रहते हुए एआई के उपयोग को सीमित करना होगा। इसी में मनुष्य के भविष्य की गुंजाइश होगी।

स्वभाषा के बिना संस्कृति निष्प्राण

हृदयनारायण दीक्षित

भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है। यूरोप की सभ्यता पर यूनानी प्रभाव है। यूनान जर्मनी से पहले सभ्य हुआ। भारत यूनान से पहले। यूनानी दर्शन ईसा के 500-600 वर्ष पहले शुरू हुआ। इसके सैकड़ों बरस पहले भारत का वैदिक दर्शन प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। यूनानी सभ्यता की विकास भूमि क्रीट द्वीप है। क्रीट की कला के विश्लेषक रैनोल्ड हिगिंस के अनुसार ईसा के 2800 बरस पहले लघु एशिया के प्रवासी वहां सभ्यता ले गए। क्रीट के क्नोसोस नगर के प्रथम शासक मिनोस के नाम पर इसे 'मिनोअन सभ्यता 'कहा गया। मिकनी नगर यूनानी सभ्यता का केन्द्र बना। यह सभ्यता मखदूनिया, साइप्रस और इटली तक फैली। मिस्र से निकाले गए हुक्सोस मिकनी के शासक थे। टायनबी ने इन्हें आर्य व हिगिंस ने इन्हें भारतीय कहा। भाषा वैज्ञानिक वामपंथी विद्वान डॉ. रामविलास शर्मा ने बताया कि, आर्य भाषा बोलने वाले भारतीय मिनोअन-मिकीनियन राज्यों के संस्थापक थे। यूनानी सभ्यता, संस्कृति और दर्शन का विकास भारतीय सम्बंधों से हुआ।

ऋग्वेद के मनु, मिस्र के प्रथम राजा मेनस और यूनान (क्रीट) के प्रथम शासक मिनोस भाषा की दृष्टि से संस्कृत के और संस्कृति की दृष्टि से भारतीय तत्व हैं। इंग्लैंड की सभ्यता यूनान से प्रेरित है। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, मिस्र से संस्कृति और सभ्यता के तत्व पाए। भारतीय संपर्क से उन्हें पुष्ट किया। अंग्रेजी स्वयं में व्यवस्थित भाषा नहीं है। संस्कृत के तमाम शब्द अंग्रेजी में हैं। संस्कृत का दिव्य ही अंग्रेजी का डिवाइन है। अंग्रेजी का ब्रदर संस्कृत का भ्रात है, फादर संस्कृत का पितृ है और मदर संस्कृत की मातृ है। गोदाम अंग्रेजी में गोडाउन है। पी.जी. सुब्बाराव ने 'इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश' में ऐसे सैकड़ों दिलचस्प शब्दों की सूची दी है। अंग्रेजों ने जर्मन, फ्रेंच से भाषा के संस्कार पाए, रोमन लिपि अपनाई।

ऋग्वेद के मनु, मिस्र के प्रथम राजा मेनस और यूनान (क्रीट) के प्रथम शासक मिनोस भाषा की दृष्टि से संस्कृत के और संस्कृति की दृष्टि से भारतीय तत्व हैं। इंग्लैंड की सभ्यता यूनान से प्रेरित है। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, मिस्र से संस्कृति और सभ्यता के तत्व पाए। भारतीय संपर्क से उन्हें पुष्ट किया। अंग्रेजी स्वयं में व्यवस्थित भाषा नहीं है। संस्कृत के तमाम शब्द अंग्रेजी में हैं। संस्कृत का दिव्य ही अंग्रेजी का डिवाइन है। अंग्रेजी का ब्रदर संस्कृत का भ्रात है, फादर संस्कृत का पितृ है और मदर संस्कृत की मातृ है। गोदाम अंग्रेजी में गोडाउन है। पी.जी. सुब्बाराव ने 'इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश' में ऐसे सैकड़ों दिलचस्प शब्दों की सूची दी है। अंग्रेजों ने जर्मन, फ्रेंच से भाषा के संस्कार पाए, रोमन लिपि अपनाई। अंग्रेजी स्वयं में व्यवस्थित भाषा नहीं है। संस्कृत के तमाम शब्द अंग्रेजी में हैं। संस्कृत का दिव्य ही अंग्रेजी का डिवाइन है। अंग्रेजी का ब्रदर संस्कृत का भ्रात है, फादर संस्कृत का पितृ है और मदर संस्कृत की मातृ है। गोदाम अंग्रेजी में गोडाउन है। पी.जी. सुब्बाराव ने 'इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश' में ऐसे सैकड़ों दिलचस्प शब्दों की सूची दी है। अंग्रेजों ने जर्मन, फ्रेंच से भाषा के संस्कार पाए, रोमन लिपि अपनाई।

भाषा विज्ञानी अलब्राइट व लैम्बिडन ने सुमेरी को प्राचीनतम लिखित भाषा बताया। इनके मुताबिक पश्चिम को सुमेरी ने प्रभावित किया। उन्होंने बताया अंग्रेजी 'ऐबिस' सुमेरी का अब्ज (पृथ्वी के नीचे का जल) है। यूनानी में वह अबुस्सास है। बेबीलोन में इसे अप्सु कहते हैं। लेकिन ऋग्वेद (1.23.19, 9.43.9 और 9.30.5 आदि) में जलवाची अप और अप्सु शब्द भरे पड़े हैं। मिस्त्री, सुमेरी और संस्कृत में भूतल जल पर एक शब्दावली है। ऋग्वेद पुराना है, जाहिर है कि संस्कृत ही सबसे पहले सृष्टि के आदि तत्व 'जल' की बोली बनी। विलियम जोन्स ने कहा कि, ''संस्कृत ग्रीक से अधिक निर्दोष, लैटिन से अधिक समृद्ध और इनमें किसी से भी अधिक उत्कृष्ट है। इसके बावजूद धातुओं और व्याकरणिक रूपों में यह इन दोनों से प्रगाढ़ सम्बंध रखती है, इतना प्रगाढ़ कि कोई भाषाविद् इनका एक ही स्रोत माने बिना छानबीन नहीं कर सकता।'' संस्कृत जाने बिना विश्व भाषा विज्ञान, विश्व भाषा परिवार, सृष्टि संरचना और विश्व सांस्कृतिक सम्बंधों का अध्ययन विश्लेषण संभव नहीं। भारत सांस्कृतिक तत्वों का भी निर्यातक था। पश्चिम एशिया में रूद्र-शिव की उपासना थी। गूर्ने ने 'दि हिटटाइटस' (पृष्ठ 134) में बताया कि वे हित्तियों के विशेष देवता थे, उनके अनेक रूप थे। सीरिया के शिल्प में वह परशु चलाते हुए बिजली कौधने के प्रतीक हैं। यूनानी (मिनोअन) संस्कृति में भी परशु खास प्रतीक हैं। इबान्स के मुताबिक यह परशु मिनोअन देवी और उसके पुरुष देवता का चिन्ह था। इसी परशु का उल्लेख ऋग्वेद में है। पश्चिमी भारत से दक्षिणी यूरोप, फिर उत्तरी यूरोप होते हुए परशु नाम का देव प्रतीक इंग्लैंड तक पहुंचा। अंग्रेजी विद्वान सम्भवतः नहीं मानते कि रुद्र का शिवत्व प्रागैतिहासिक काल में भी है। ऋग्वेद में वे अरुण-रूद्र हैं। वे जटाधारी भी हैं। यजुर्वेद में वे नमः शम्भवाय-नमः शिवाय भी हैं। जैसे सीरिया में वे बिजली कौधने के प्रतीक हैं वैसे ही उसके बहुत पहले ऋग्वेद (7.46.3) में वे आकाश से बिजली गिराते हैं। यहां उनसे अमृत्व की महामृत्युंजय स्तुति (7.59.12) है।

सभ्यता, संस्कृति, देवतंत्र, दर्शन, भौतिकी और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का आदि केन्द्र भारत है। यूरोपीय विद्वान एच.एस. मेन ने लिखा था, बीजगणित, अंकगणित में पश्चिमी सहायता के बिना ही ऊंचे दर्जे की दक्षता है। दशमलव प्रणाली के अविष्कार का हम पर ऋण है। अरबों ने अंक हिन्दुओं से पाए, यूरोप में फैलाए। यूरोपीय चिकित्सा पद्धति 17वीं सदी तक अरबी चिकित्सा थी।

विलियम हंटर ने लिखा था कि, ''पश्चिम के विद्वान जब भाषा विज्ञान का विवेचन आकस्मिक समानताओं के आधार पर कर रहे थे, उस समय भारत में व्याकरण को मूल सिद्धांतों का रूप मिल चुका था।

सारा ज्ञान विज्ञान, संस्कृति दर्शन संस्कृत में है, हिन्दी में भी है। बावजूद इसके अंग्रेजी पर जोर है, अंग्रेजी का शोर है। सवाल यह है कि जो संस्कृत और हिन्दी काव्य, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, प्रीति और प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है, वही विज्ञान और व्यापार की सशक्त भाषा क्यों नहीं है?

भारत प्राचीनतम व अद्वितीय राष्ट्र है। मैक्समूलर ने लिखा, भारत के मानवी-मस्तिष्क ने कुछ सर्वोत्तम गुणों का पूर्ण विकास किया है। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं पर भारत द्वारा प्राप्त हल प्लेटो और कांट के दर्शन का अध्ययन किए हुए लोगों के लिए (भी) विचार करने योग्य है। यूनानी, रोमन और एक सेमेटिक जाति यहूदी के विचार मात्र पर पालित-पोषित यूरोप के हम लोग जीवन को अधिक परिपक्व, अधिक व्यापक, अधिक सार्वलौकिक, दरअसल सच्चे मानवीय बनाने के लिए भारत की ओर ही देखते हैं। भारतीय संस्कृति दर्शन की ऐसी प्रतिष्ठा पर गर्व करना चाहिए।

स्वाधीनता संग्राम की भाषा मातृभाषा हिंदी थी लेकिन नए प्रभुवर्ग अंग्रेजी को वरीयता देते रहे हैं। गांधीजी ने कहा था, ''अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया है। मैं इसे अपने देश और मनुष्यत्व के प्रति अपराध मानता हूं।'' (संपूर्ण गांधी वांगमय 29-312) संस्कृति, सृजन और संवाद की भाषा हिंदी है। बावजूद इसके अंग्रेजी का मोह बढ़ा, अंग्रेजी स्कूल बढ़े, अंग्रेजी प्रभुवर्ग की भाषा बनी। हिंदी का अंग्रेजीकरण भी हुआ।

भारत, रूस और अमेरिका के बीच नए समीकरण

ललित मोहन बंसल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पेरिस और वॉशिंगटन दौरे के बाद आस बंधी है कि भारत में अनवरत विद्युत और गैस सप्लाई से आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी। एक समय उद्यमी अपने कल-कारखाने में उत्पादन कार्य से पहले अनवरत विद्युत सप्लाई के लिए भागदौड़ में जुटा रहता था। आज एक ओर क्लाइमेट चेंज के कारण कार्बन रहित विद्युत उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, वहीं आणविक विद्युत सप्लाई के लिए बड़े संयंत्र की जगह छोटे आणविक संयत्रों की मांग बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के पहले पड़ाव में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो से द्विपक्षीय वार्ता में रिन्युअल एनर्जी के अंतर्गत छोटे आणविक संयंत्रों की सप्लाई पर अहम समझौता कर कार्बन रहित संस्कृति को गति दी है। इससे निःसंदेह मोदी के 'मेक इन इंडिया' मंत्र को नई दिशा मिलेगी, वहीं देश के विभिन्न राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चौबीसों घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति की जरूरत होगी, जो डाटा सेंटर और विशाल कंप्यूटर सेंटर को सजीव रख सके। भारत के आर्थिक विकास में ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति एक प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में भारत की ऊर्जा, विशेषकर कच्चे तेल की माँग चीन से ज्यादा होगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मानें तो निःसंदेह तीन सालों में भारत के कारोबार में वृद्धि होने से परिवहन और उद्योग में कच्चे तेल की माँग बढ़ेगी, एक तेजी से खड़ी होने वाली भारतीय इकॉनमी के लिए परिष्कृत ऊर्जा और और विद्युत ऊर्जा की जरूरत होगी। पेरिस आधारित इस एजेंसी के अनुसार भारत को मौजूदा 15.380 करोड़ बैरल से बढ़ कर 2030 में 16.640 करोड़ बैरल प्रतिदिन की जरूरत होगी। मोदी ने वार्ता के दौरान अगले पाँच सालों में विकसित भारत-2047 तक दोगुने व्यापार की उम्मीद जताई है। बता दें, मोदी और ट्रम्प वार्ता के दौरान व्यापार संधि में भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने पर सहमति जताई है। भारत अमेरिका से कितना तेल और गैस खरीदेगा, इस पर विचार जारी है। दुनिया में कच्चे तेल के आयात में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा बड़ा आयातक देश है।

मोदी-ट्रम्प वार्ता में ऊर्जा : कच्चे तेल पर आधारित भारतीय इकॉनामी को पाँच खरब की इकॉनामी बनने के लिए अमेरिका से होकर क्षितिज पर पहुँचना होगा। दुनिया में तेल के आयात में भारत तीसरा (10.1 ब्र) बड़ा देश है। भारत ने 2023-24 में 88ब्र तेल के आयात पर निर्भर रहा। 2023-24 में कच्चे तेल का बिल 139.3 अरब डॉलर था, जो भारत के कुल आयात मूल्य 678 डॉलर का 21 प्रतिशत कहा जा सकता है। इसमें तेल आधारित उत्पाद नहीं है। भारत खुद तेल आधारित उत्पाद बना कर यूरोपीय देशों को निर्यात करता है और 23.3 अरब डालर अर्जित करता है। इसमें एलपीजी 10.5 अरब डॉलर, 22.1 अरब डॉलर के हाई स्पीड डीजल और 11.2 अरब डॉलर मोटर स्पिरिट है। ऐसे में कच्चे तेल की क़ीमतें गिरती हैं, निश्चित तौर पर भारत लाभान्वित होगा।

अभी तक तेल की कीमतों को प्रभावित करने में खाड़ी में तेल उत्पादक देशों और ओपेक प्लस देशों में रूस, अमेरिका सहित ऐसे आधा दर्जन देश हैं, जो तेल का उत्पादन करते हैं। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन अल्प मात्रा में हो पाता है, जबकि उसे अठासी प्रतिशत तक आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत तेल की कीमतों को प्रभावित करने की स्थिति में भले नहीं रहा, वह भू-राजनैतिक कारणों से सऊदी, ईरान, इराक़ और यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुएला आदि देशों से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति करता रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के से उपजी परिस्थितियों के कारण भारत ने राष्ट्रहित में मौजूदा निर्यातक देशों के कोटे में कटौती कर अधिकाधिक तेल रूस से खरीदना शुरू किया। रूस और भारत के रणनीतिक रिश्तों के कारण भारत में कच्चा तेल 15 से 20 डॉलर प्रति बैरल आयात किया जाता रहा है। शुरू में 2023-24 में 33 ब्र इराक़, 21ब्र सऊदी अरब, 16ब्र यूएई, 6.4 ब्र खाड़ी के ओपेक प्लस देशों में रूस और अमेरिका, दो बड़े देश हैं, जो दस लाख बैरल तेल प्रतिदिन निकालते हैं, हालांकि अमेरिकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका सऊदी अरब जैसे दोस्तों से तेल की आपूर्ति करता है। भारत ने यूएस से तेल के आयात पर सहमति देकर एक ओर अमेरिका से मित्रता का धर्म निभाया है, वहीं खाड़ी और रूस से आयात के मौजूदा कोटे में कमी कर देश को चुनौतियों के लिए आमंत्रण दिया है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रम्प कच्चे तेल का अधिकाधिक उत्पादन करना चाहते हैं। वह अपने तेल उत्पादकों से कहते हैं, 'ड्रिल बेबी ड्रिल' और दूसरी ओर मित्र देशों को उलाहना देते हुए कहते हैं, 'आओ, हमसे दोस्ती करो और तेल पाओ।' ' अमेरिका ने 29023 में 19358 हज़ार बैरल प्रतिदिन उत्पादन किया, जो वैश्विक स्तर पर कुल उत्पादन का 20.1 ब्र है। ओपेक देशों का 35.3 ब्र और ओपेक + देशों रूस और मैक्सिको सहित 54ब्र है। ऐसे समय जब रूस अपनी जर्जर इकॉनामी को सुधारने के लिए भारत को सस्ते में तेल देने का प्रलोभन देता है, तो ग़लत नहीं है।